मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,

सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णत: पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 9 DECEMBER TO 15 DECEMBER 2020 • VOLUME- 20 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD

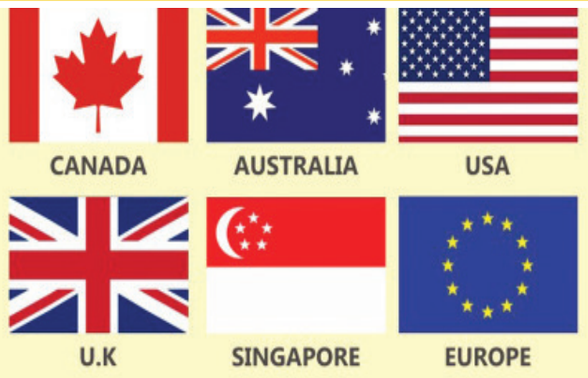

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर, पीएम WiFi को मिली मंजूरी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

देश में जारी किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई नेटवर्क को लाने के लिए पीएम-वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस-लॉन्च करने का निर्णय लिया है। देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और पूरी योजना अवधि के लिए रु 2,810 करोड़ यानी 2020-2023; लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना है।

कैबिनेट बैठक पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है।

राहुल ने साधा निशाना, कहा- सरकार लोकतंत्र से पाना चाहती है छुटकारा

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''श्रीमान मोदी के कार्यकाल में सुधार, चोरी के जैसा है। इसलिए वे लोकतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं।'' नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मंगलवार को एक डिजिटल कार्यक्रम में बयान देने के बाद गांधी ने ट्वीट किया।

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह लोकतंत्र से छुटकारा पानी चाहती है। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सुधार, चोरी के जैसा है। गांधी ने ट्वीट किया, ''श्रीमान मोदी के कार्यकाल में सुधार, चोरी के जैसा है। इसलिए वे लोकतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं।'' नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मंगलवार को एक डिजिटल कार्यक्रम में बयान देने के बाद गांधी ने ट्वीट किया।

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा था कि भारत में 'कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है' जिसके कारण यहां कड़े सुधारों को लागू करना कठिन होता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि देश को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये और बड़े सुधारों की जरूरत है। स्वराज्य पत्रिका के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये संबोधित करते हुए कांत ने कहा था कि पहली बार केंद्र ने खनन, कोयला, श्रम, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में कड़े सुधारों को आगे बढ़ाया है। अब राज्यों को सुधारों के अगले चरण को आगे बढ़ाना चाहिए।

राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले जावड़ेकर, किसान कृषि सुधार पर लगी मुहर

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान के पंचायत चुनाव के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसानों का फैसलों की मुहर करार दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यत: किसान 2.5 करोड़ वोटर थे, उनका ये फैसला है। जावड़ेकर ने कहा कि जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें 353 सीटें भाजपा ने जीती हैं। 21 जिला परिषदों में चुनाव हुआ, जिसमे से 14 में भाजपा को बहुमत मिला है और कांग्रेस को केवल 5 में बहुमत मिला है। इन चुनावों में 2.5 करोड़ वोटरों में से अधिकतर किसान हैं, इसका मतलब है कि किसान राजस्थान में कृषि सुधारों के पक्ष में

हैं तेलंगाना में अभी हुए हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को 49 सीटें मिली जबकि सत्तारूढ़ TRS को 55 सीटें मिली। इसके साथ ही जावड़ेकर ने जोर देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा को TRS से अधिक वोट मिले। अरुणाचल में भाजपा को भारी सफलता मिली है। 240 जिला पंचायत के चुनावों में 96 सीटें निर्विरोध आई हैं। ग्राम पंचायत में 8,291 सीटों में से 5,410 सीट निर्विरोध आ गई हैं। राजस्थान के चुनाव में इस बार हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के गृह जिले टोंक में जिला परिषद भाजपा ने जीती है। आने वाले समय के लिए ये शुभ संकेत है कि मतदाता दक्षिण हो या पूर्वोत्तर हो, सभी जगह भाजपा के पक्ष में है। कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक संकट और विपक्ष का कृषि सुधारों पर दुष्प्रचार के बाद भी मतदाता सभी जगह भाजपा को पसंद कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में तीन आतंकियों को किया ढेर

■ श्रीनगर/ब्यूरो

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आंतकवादियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में एक असैन्य नागरिक घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया

जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज तड़के पुलवामा जिले के टिकन इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में पहले दो आतंकवादी मारे गए और एक असैन्य नागरिक घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बार मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों और उनके संगठन की पहचान की जा रही है।

किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज किया, जारी रहेगा प्रदर्शन

जानें क्या है आगे का प्लान

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने कहा कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि दोबारा प्रस्ताव आएगा तो हम उसपर विचार करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन तेज करेंगे। 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे।

12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे सील रहेगा। दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। 12 दिसंबर तक टोल प्लाजा को फ्री करेंगे।

कानून रद्द किए जाने तक जंग जारी रहेगी। किसानों के कड़े रुख

के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं।

सरकार का प्रस्ताव

इससे पहले किसान संगठनों के एक प्रतिनिधि समूह को सरकार की ओर से एक मसौदा प्रस्ताव मिला जो प्रदर्शनकारियों की कुछ मुख्य चिंताओं से जुड़ा हुआ है। मसौदा प्रस्ताव 13 कृषक संगठन नेताओं को भेजा गया जिनमें बीकेयू (एकता उगराहन) के जोगिंदर सिंह उगराहन भी शामिल हैं। यह संगठन करीब 40 आंदोलनकारी संगठनों में से सबसे बड़े संगठनों में शामिल है। प्रस्ताव मिलने के बाद किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान संगठनों ने आगे के रुख की जानकारी दी।

फगवाड़ा स्थित चहेरु में हाईवे प्लाजा के कलोनाईजर के ऊपर किसी भी वक्त हो सकता है पर्चा दर्ज

जेडीए ने रिजेक्ट की कॉलोनी

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर डवैल्पमैंट अथॉरिटी जिसमें म्युनिसिपल लिमिट के बाहर का क्षेत्र पड़ता है लेकिन अपने विभाग को अच्छे से संभालने में विफल साबित हुई है। यहाँ पर तैनात अधिकारी सिर्फ उन लोगों को नोटिस निकालने में या तंग करने में लगे हैं जिन्होंने अवैध कोलोनियों में अपने खून पसीने की कमाई से छोटे-छोटे कमर्शियल और रिहायशी प्लाट खरीदे हैं और उन्होंने पुडा के विभाग से अपने नक्शे भी पास करवाए है पर अगर उनसे कोई नक्शे के बाहर कोई अनाधिकृत निर्माण किया जाता है तो उन्हें विभाग द्वारा नोटिस भेज के 7 दिन के अंदर ठीक करने के लिया कहा जाता है यह सब कुछ आम लोगों के लिए ही किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों के ध्यान में कई बार लोगों द्वारा जिन्होंने अवैध कॉलोनी में सरकार से अपने प्लाट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया हुआ है और सरकार द्वारा अपनी बनाई गई पॉलिसी में साफ लिखा गया है कि जैसे ही प्लाट होल्डर के पैसे विभाग में जमा हो जायेंगे तो विभाग द्वारा वहां रह रहे लोगों को पॉलिसी की मुताबिक मूलभूत सुविधा दी जाएगी और जहाँ कलोनाईजर को सरकार द्वारा दिए गए टाइम के अंदर अपनी कॉलोनी के पैसे जमा करवाने थे अगर वो ऐसा नहीं करता तो विभाग उसके खिलाफ एफ.आई.आर. के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को लिख सकता है।

जेडीए द्वारा रिजेक्ट की गई हाईवे प्लाजा कालोनी।

पुडा विभाग

इसी कड़ी में जब फगवाड़ा स्थित चहेरु-महेरु में बनी दो कलोनियों के बारे में विभाग से लोगों को सड़कें और बाकी सुविधा देने के लिए कहा गया लेकिन जवाब में विभाग द्वारा महेरु स्थित सिमर एन्क्लेव को रेगुलर करने के लिए विचारधीन रखा हुआ है और दूसरी तरफ चहेरु स्थित हाईवे प्लाजा को विभाग द्वारा रिजेक्ट करके उसके कलोनाईजर के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए लिखा गया है।

अब यह देखना होगा कि आम लोग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे है उनको मूलभूत सुविधाएँ विभाग के कर्मचारी दिलवा पाएंगे या नोटिस और एफ.आई.आर सिर्फ आम लोगों के लिए ही रखी हुई है। क्या विभाग और अधिकारी बड़े-बड़े कलोनाईजरों के आगे झुकेंगे या लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाएंगे?

दखल

अर्थव्यवस्था में भरोसे का संकट

भारत की जीडीपी में उपभोक्ता खर्च की हिस्सेदारी साठ फीसद से अधिक है। जबकि रोजगार की दर गिर कर 36.2 फीसद हो गई है, यानी श्रमशक्ति का 63.8 फीसद हिस्सा बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है, उनकी भी कमाई घट गई है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को मजबूत कर भरोसे वाली अर्थव्यवस्था का भरोसेमंद मॉडल विकसित करना होगा, ताकि भरोसा हमेशा बना रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे।

भरोसा एक ऐसा शब्द है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी पर दुनिया टिकी है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब भरोसे पर टिका है। भरोसा है तो व्यवस्था चलती है, भरोसा उठ गया तो सब ठप हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी यह उपयुक्त लगता है। भरोसा डगमगाते ही अर्थ की व्यवस्था डगमगाने लगती है। इसलिए अर्थ और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि लोगों का इस पर भरोसा बना रहे। कोरोना विषाणु के प्रकोप बाद अर्थव्यवस्था लुढ़क कर गहरी खाई में चली गई। पहली तिमाही में देश की जीडीपी दर इतिहास में पहली बार शून्य से नीचे 23.9 फीसद पर पहुंच गई। दूसरी तिमाही में इसमें सुधार जरूर हुआ, लेकिन अभी भी यह शून्य से नीचे साढ़े फीसद पर है। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि अर्थव्यवस्था औपचारिक रूप से मंदी में जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का हालांकि कहना है कि सुधार की मौजूदा रफ्तार बनी रही तो तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल आएगी। लेकिन इस रफ्तार के बने रहने के संकेत फिलहाल नहीं हैं।

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी और नीचे जा सकती है, क्योंकि दूसरी तिमाही का सुधार त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने के कारण हुआ है, जिसके तीसरी तिमाही में बने रहने की संभावना नहीं है। उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा कोरोना से पहले ही डगमगाने लगा था। वित्त वर्ष 2018-19 में 6.1 फीसद की वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 फीसद पर आ गई। लेकिन कोरोना के बाद भरोसा उठ-सा गया। आरबीआई के उपभोक्ता भरोसा सर्वेक्षण के अनुसार, सितंबर में अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआइ) रिकार्ड निचले स्तर 49.9 पर चला गया। इसके पहले जुलाई में यह 53.8 पर और मई में 63.7 पर था। पिछले दस सालों के दौरान 2010 की चौथी तिमाही में उपभोक्ताओं का भरोसा 116.70 के सर्वोच्च स्तर पर था। उस दौरान (2010-11 की चौथी तिमाही में) जीडीपी वृद्धि दर 9.2 फीसद थी। हालांकि अगले साल यानी 2021 को लेकर उपभोक्ता आशावान हैं, क्योंकि अगस्त-सितंबर के सर्वेक्षण में भविष्य उम्मीद सूचकांक (एफईआइ) 115.9 पर था, जो जुलाई में 105.4 और मई में 100 से नीचे चला गया था। इस सूचकांक के 100 से नीचे जाने का अर्थ होता है कि भविष्य की स्थिति वर्तमान से भी खराब हो सकती है।

शायद सितंबर के एफईआइ के आधार पर ही कहा जा रहा है कि अगली तिमाही में या अगले साल अर्थव्यवस्था मंदी से उबर जाएगी। लेकिन यह सिर्फ उम्मीद है, और जब तक यह भरोसे में नहीं बदल जाती, सुधार का जश्न बेमानी है। सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं की उम्मीद भरोसे में कैसे बदलेगी? उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था पर भरोसा तब बढ़ता है, जब उन्हें आमदनी का भरोसा हो जाए, यानी उनके पास रोजगार हो, नौकरियां हों। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि श्रम बाजार में रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है और रोजगार दर 2016-17 (42.8 फीसद) से ही लगातार नीचे जा रही है। पिछले महीने यानी नवंबर के प्रथम सप्ताह में 37.5 फीसद, दूसरे सप्ताह में 37.4 फीसद और 22 नवंबर को समाप्त तीसरे सप्ताह में रोजगार दर लुढ़क कर 36.2 फीसद पर चली गई। अब तीसरी तिमाही के दो महीने बीत चुके हैं और रोजगार दर की यह हालत है। ऐसे में उपभोक्ताओं की उम्मीद को भरोसे में बदलने की उम्मीद कैसे की जाए?

तीसरी तिमाही में तो संभावना न के बराबर है। रोजगार दर नीचे होने का मतलब है उपभोक्ताओं के पास आमदनी नहीं है। आमदनी न होने पर जाहिर-सी बात है वे खरीदारी नहीं करेंगे और बाजार में मांग नहीं होगी। फिर उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो नौकरियां पैदा नहीं होंगी। यह स्थिति अधिक अवधि तक बनी रहती है तो जीडीपी का आकार घटने लगता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। पिछले वित्त वर्ष (2019-20) में भारत की जीडीपी 2.94 खरब डॉलर थी और देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब 2020 में भारत की जीडीपी का आकार घट कर 2.6 खरब डॉलर होने की बात कही जा रही है और देश अब एक पायदान नीचे खिसक कर दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था होगा। उत्पादन कम होने और मांग अधिक होने से महंगाई बढ़ती है। लेकिन इस समय मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर छह साल के उच्चस्तर 7.61 फीसद पर पहुंच गई।

सबसे बड़ा आश्चर्य खाद्य महंगाई दर को लेकर है, जो अक्टूबर में बढ़ कर 11.07 फीसद हो गई। जबकि कृषि विकास दर दूसरी तिमाही में भी 3.4 फीसद पर बनी हुई है और सरकार के अनुसार अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था की इस स्थिति को मुद्रास्फीतिजनित मंदी कहते हैं। तो भारत सिर्फ मंदी ही नहीं, बल्कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की चपेट में है। इस मंदी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भरोसा ही है। लेकिन सवाल उठता है कि उपभोक्ताओं में यह भरोसा जागेगा कैसे और इसे कौन जगाएगा? भारत की जीडीपी में उपभोक्ता खर्च की हिस्सेदारी साठ फीसद से अधिक है। जबकि रोजगार की दर गिर कर 36.2 फीसद हो गई है, यानी श्रमशक्ति का 63.8 फीसद हिस्सा बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है, उनकी भी कमाई घट गई है।

परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का भरोसा रिकार्ड निचले स्तर 49.9 पर चला गया है। इस भरोसे को ऊपर उठाने के सिवाय अर्थव्यवस्था को उबारने का दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में हमें यह देखना होगा कि कहां क्या किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने उपाय किए भी हैं। लेकिन अब तक किए गए उपाय अपेक्षित परिणाम देते नजर नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर उपाय निजी क्षेत्र के उद्यमों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाले रहे हैं। जबकि निजी क्षेत्र सिर्फ बाजार में मांग बढ़ने से प्रोत्साहित होता है। हां, जहां सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सीधे तौर पर उपाय किए हैं, वहां परिणाम दिखा है। मनरेगा के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों के भत्तों में भले कटौती हुई हो, लेकिन नौकरियां नहीं गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ने कोरोना काल में शानदार काम किया है। कमजोर ढांचे के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य महकमे ने ही कोरोना से लोहा लिया। कृषि क्षेत्र ने इस संकट में सुरक्षा कवच का काम किया है। अर्थव्यवस्था के खाई में लुढ़क जाने के बावजूद कृषि क्षेत्र में लगातार दो तिमाही से 3.4 फीसद की वृद्धि दर बनी हुई है।

जब देश पर संकट आता है तो यही निजी क्षेत्र मददगार बनने के बदले अपने दरवाजे बंद कर घर के अंदर बैठ जाता है। यह अलग बात है कि निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तात्कालिक वृद्धि दर मुहैया कराता है, लेकिन अर्थव्यवस्था चक्र में थोड़ा-सा व्यवधान आने पर अर्थव्यवस्था को उसी रफ्तार से नीचे भी पहुंचा देता है। भरोसेमंद उसी को माना जाता है, जो संकट में साथ दे। लिहाजा हमें सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को मजबूत कर भरोसे वाली अर्थव्यवस्था का एक भरोसेमंद मॉडल विकसित करना होगा, ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा हमेशा बना रहे और अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे।

विचार

एमएसपी बना गले की फांस

किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद के बाद अब नजर समाधान पर टिकी है। सरकार कानून में बदलाव को तैयार है, तो किसान चाहते हैं कानून को रद्द किया जाए। मामला अब प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है तो दोनों ही पक्षों को बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा।

तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए चल रहे किसान आंदोलन ने भारत बंद भी करा लिया। बावजूद इसके समाधान के आसार नहीं दिख रहे हैं। 9 दिसंबर को एक बार फिर सरकार से वार्ता का दौर तय है, यह मुकाम पर पहुंचेगा या नहीं, कहना कठिन है। दरअसल, आंदोलन में मुख्य पेंच न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी को लेकर बना हुआ है। एमएसपी के सवाल पर आंदोलनकारी किसान संगठन ही नहीं बल्कि संघ के अनुषांगिक संगठन भी सरकार के खिलाफ हैं। हालांकि इस मांग से जुड़ी जटिलताओं के कारण सरकार पूरी तरह असमंजस में है। अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा कर दी जाए तो तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग संबंधी स्वर धीमे हो सकते हैं क्योंकि सरकार पहले से ही इन कानूनों के कई प्रावधानों में संशोधन के लिए तैयार है। सरकार किसानों को सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने, एनएसआर क्षेत्र से जुड़े नए प्रदूषण कानून में बदलाव करने, निजी खरीददारों के लिए पंजीयन अनिवार्य करने और छोटे किसानों की हितों की रक्षा के प्रावधानों में बदलाव को तैयार है।

पांचवें दौर की बैठक के बेनतीजा रहने के बाद सरकार में आंदोलन खत्म कराने के लिए माथापच्ची जारी है। मुख्य चिंता एमएसपी को लेकर है। कृषि मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच शनिवार रात से ही कई दौर की बातचीत हुई है। इस पर अंतिम निर्णय से पहले सरकार किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के जरिए उनका दमखम भी देख चुकी है। आजादी के बाद से ही सरकारें किसान और ग्राहकों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में नाकाम रही हैं। इसके कारण ग्राहकों को तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, मगर ग्राहक के द्वारा चुकाई गई रकम का मामूली हिस्सा ही किसानों की जेब तक पहुंचा। मसलन ग्राहकों ने कई बार किसान द्वारा बेची गई रकम से चार से पांच गुना अधिक कीमत चुकाई। कृषि क्षेत्र का मुनाफा बिचौलियों की भेंट चढ़ता रहा। आजादी के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकारें किसानों का आय बढ़ाने में नाकाम रही। केंद्र सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की है। एमएसपी को सरकार कानूनी तो बना देगी, मगर निजी क्षेत्र को खरीदारी के लिए बाध्य नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर फसल की मांग कम हुई तो निजी क्षेत्र खरीदारी करेंगे ही नहीं।

सरकार एक सीमा तक ही एमएसपी के तहत खरीदारी कर सकती है। सरकार औसतन कुल उपज का छह फीसदी की ही खरीद करती है। वर्तमान क्षमता के अनुरूप इसे दस फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। भंडारण क्षमता, अर्थव्यवस्था पर बोझ सहित कई ऐसे कारण है जिसके चलते सरकार अधिक मात्रा में अनाज नहीं खरीद सकती। किसी एक फसल की अधिक उपज होने के बाद उसकी मांग में कमी आएगी। सरकार एक सीमा से अधिक फसल नहीं खरीदेगी। सरकार हर मांग मानने को तैयार है, किसान भी जिद छोड़ें।

बचाना होगा छोटी नदियों को

छोटी नदियों पर संकट का निदान उसके संरक्षण में है। नदियों का संकट में होना संकट का कारण बन सकता है। 1951 में प्रति व्यक्ति चौदह हजार लीटर पानी सहजता से उपलब्ध था। लेकिन अनुमान है कि 2050 तक पानी की उपलब्धता तीन हजार लीटर प्रतिव्यक्ति ही रह जाएगी। यह स्थिति डराती है। ऐसे में समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम नदियों के प्रति संवेदनशील हों, अन्यथा आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे।

आमतौर पर गर्मी ऋतु में देश के कई हिस्सों से इस आशय की खबरें आती हैं कि छोटी नदियां सूख गईं या कुछ बड़ी नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में बहने वाली उजाड़ नदी इस वर्ष नवंबर महीने में ही सूख गई। उजाड़ चंबल की सहायक नदी है और अंचल के बहुत सारे गांवों के लिए जीवनरेखा है। आमतौर पर उजाड़ नदी में इतना पानी रहता था कि उससे जुड़े गांवों में आवागमन सुनिश्चित करने के लिए 55 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। लेकिन अपने जल से इलाके को विकास का वरदान सौंपने वाली यह नदी समाज की अपने प्रति असंवेदनशीलता के कारण अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए छटपटाती-सी प्रतीत होती है।

दरअसल, अपने प्रति संवेदनहीनता का दंश झेल रही उजाड़ नदी देश की अकेली नदी नहीं है। देश में ऐसी सैकड़ों सहायक नदियां होंगी जो इस तरह असमय सूख कर दम तोड़ रही हैं और मनुष्य के लिए जल संकट के खतरे की घंटी बजा रही हैं। लेकिन लगता है हम इस खतरे को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंगा को तो हमारी मान्यताओं में बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को अंतिम समय यदि गंगाजल की दो बूंदों का भी आचमन मिल जाए तो सांसारिक बंधनों से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन देवी माने जाने वाली गंगा नदी स्वयं अब प्रदूषण के दुर्दांत प्रतीत होते असुर से संघर्ष करने पर विवश है। पिछले दिनों यमुना में प्रदूषण के कारण उठे झागों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चलीं। सदा सलिला कही जाने वाली चंबल नदी के पानी को भी परीक्षण में कई स्थानों पर पीने योग्य नहीं पाया गया है।

कावेरी नदी 40 प्रतिशत से अधिक अपना जलप्रवाह खो चुकी है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी में पानी की मात्रा दो दशक पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। जब देश की महनीय नदियों का यह हाल है तो छोटी नदियों और बरसाती नदियों की स्थिति का अनुमान तो आसानी से लगाया जा सकता है। यह स्थिति इसलिए चिंता पैदा करती है क्योंकि हमारी पानी की जरूरत का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नदियां ही पूरा करती हैं। पानी केवल पीने या रोमजर्रा की जरूरतों को पूरा करने या सिंचाई के काम ही नहीं आता, अपितु औद्योगिक उत्पादन में कच्चे माल के परिशोधन सहित अनेक क्रियाओं में पानी ही जरूरी होता है। ऐसे में जिन देशों को प्रकृति ने नदियों का वरदान दिया है, उन्हें नदियों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत थी।

लेकिन दुर्भाग्य से विकास की आपाधापी ने नदियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को छीन लिया। हमने नदियों को बचाने और संरक्षित रखने के बजाय के उनके प्रवाह क्षेत्र में ही बस्तियां बनानी शुरू दीं।

यह तो समझ आता है कि नदियों के प्रवाह पर बांध बनाना जीवन की जरूरत था, लेकिन नदियों के किनारों पर अतिक्रमण कर लेना या उनमें मनमाने तरीके से गंदगी प्रवाहित करना कैसे उचित कहा जा सकता है? स्थिति यह हो गई कि हम नदियों को देवी मान कर पूजते तो रहे, लेकिन उनकी पवित्रता से खिलवाड़ भी करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नदियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भारत में ही हुआ। अपने सीमित संसाधनों से आकाश की अथाह ऊंचाई नापने की आपाधापी में कई विकासशील देशों ने नदियों की महत्ता को नजरअंदाज किया है। ब्राजील के रियो-दे जेनेरियो की सारापुई या सुपुई नदी कचरे से इस कदर भर गई है कि उस पर पैदल चला जा सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंडों से कोई न कोई नदी गुजरती है। लेकिन इन नदियों में से अधिकांश अपनी दुर्दशा पर आंखें बहा रहीं हैं। नदियों की अत्यधिक संख्या के कारण मिथिला को तो नदियों का मायका तक कह दिया जाता है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि नदियां अपने मायके में ही दुख के साथ बह रही हैं। बिहार की बूढ़ी गंडक, लखनदेई, टिमदा, झझा, सियारी, कदाने, बाया, डंडा, मनुषमारा जैसी नदियां या तो दम तोड़ चुकी हैं या दम तोड़ने के कगार पर हैं।

झारखंड में पिछली गर्मियों में 133 नदियों के सूखने की खबरें आई थीं। पलामू जिले की ही कोयल, सदाबह, अमानत नदियां अस्तित्व के लिए जूझती दिखीं। गुमला जिले में नदी के प्रवाह क्षेत्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखे। किसी नदी के सिकुड़ने या सूखने का दर्द क्या होता है, यह उन इलाकों में जाकर जानना चाहिए जिन इलाकों ने इस स्थिति का सामना किया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से बेहतर किसी नदी के महत्त्व को कहां समझा जा सकता है? कहते हैं कि पौराणिक नदी सरस्वती का प्रवाह इसी क्षेत्र में था। शोधकर्ताओं के अनुसार करीब 150 पहले भी राजस्थान के इस इलाके के प्रमुख शहर बीकानेर के पास नाल गांव में एक नदी बहती थी, लेकिन धीरे-धीरे वह लुप्त हो गई। जर्मनी के द मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस आफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा और शोध संस्थान (आइआइएसईआर) जैसे संस्थानों से जुड़े विद्वानों ने यह शोध किया था। इससे कुछ ही दूर स्थित सीकर जिले की साइवार की पहाड़ियों से निकलने वाली साहबी नदी की तो सौ से अधिक उपनदियां थीं। इस नदी के प्रवाह का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर मासनी बांध बनाया गया। लेकिन यह नदी भी अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

कुछ विद्वानों ने पौराणिक दृष्दावती नदी के रूप में इसे पहचाना है। सोता, कृष्णावती, दोहन आदि इस नदी की उपनदियां थीं। एक नदी के रूठने के डर से दन दिनों दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे भी गुजर रहा है। यहां की राजधानी असुनशियोन के पास से गुजरने वाली नदी पराग्वे ही इस देश को समुद्र से जोड़ने वाला एकमात्र विकल्प थी। इस देश के लिए पराग्वे नदी के महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी नदी के नाम पर देश का नाम भी रखा गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी-नासा द्वारा पिछले दिनों जारी एक तस्वीर में यह दिखाया गया है कि कैसे राजधानी असुनशियोन के आसपास नदी का इलाका सूख गया है। पराग्वे के लोक निर्माण विभाग के निदेशक जॉर्ज वेगार्रा ने पिछले दिनों कहा भी कि 'नदी सूखने का असर सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि पराग्वे का 52 फीसद आयात और लगभग 75 प्रतिशत निर्यात नदी के रास्ते से ही होता है।' नदी के सूखने ने दूरस्थ इलाकों की बस्तियों में पेयजल आपूर्ति को भी प्रभावित किया है।

नदियां मानव सभ्यता की उन्नायक रही हैं। प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी नदी घाटी में हुआ है। लेकिन अब नदियां संकट में हैं। नदियों का संकट में होना आमजन के लिए भी संकट का कारण बन सकता है। सन 1951 में हमारे यहां प्रतिव्यक्ति चौदह हजार 180 पानी सहजता से उपलब्ध था। लेकिन अनुमान है कि सन 2050 तक पानी की उपलब्धता तीन हजार एक सौ बीस लीटर प्रतिव्यक्ति ही रह जाएगी। यह स्थिति डराती है। देश में जहां छोटी नदियों के प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमण के शिकार हो गए हैं, वहीं 265 मझोली नदियां संकट में हैं। बड़ी नदियां भी प्रदूषण का शिकार हो रही हैं।

ट्विटर

सरकार किसान कानूनों को रद्द करे और आंदोलन को खत्म कराए। आज देश की जो हालत है, वह सरकार की हठधर्मिता का परिणाम है। सरकार जिद छोड़े।

सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष

विपक्ष किसानों का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। विपक्ष को अगर किसानों की चिंता होती तो इस तरह के बदलाव पहले ही हो जाते।

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री

सत्यार्थ

गरीबों की सेवा ही तीर्थयात्रा

अपनी हज यात्रा पूर्ण कर एक दिन अब्दुला बिन मुबारक काबा में ही सोए हुए थे। तभी उन्होंने सपने में दो फरिश्तों को आपस में बातें करते हुए देखा। एक फरिश्ते ने पूछा -इस साल हज के लिए कितने लोग आए और उनमें से कितनों की दुआ कबूल हुई? दूसरे फरिश्ते ने कहा- वैसे तो हज करने को लाखों लोग आए थे, मगर इनमें से दुआ किसी की भी कबूल नहीं हुई। इस वर्ष दुआ सिर्फ एक की ही कबूल हुई है और वह भी ऐसे इंसान की है, जो यहां आया भी नहीं था। यह सुनकर पहले फरिश्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस ने हैरानी से पूछा-भला वह कौन ऐसा खुशनसीब है, जो कि यहां आया भी नहीं और उसकी दुआ भी कबूल हो गई? तब दूसरा फरिश्ता बोला- वह है दमिश्क का मोची अली बिन मूफिक। फरिश्तों की ये बातें सुनकर अब्दुला ने सोचा कि उस पाक हस्ती से जरूर मिलना चाहिए। मोची से मिलने को अब्दुला अगले ही दिन दमिश्क के लिए चल पड़े और वहां उनका घर भी ढूंढ लिया।

अब्दुला बिन मुबारक ने मोची से पूछा-क्या तुम हज को गए थे? इतना सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। न में सिर हिलाते हुए कहा- मेरा मुकद्दर कहां, जो हज को जा पाता! जिंदगी भर की मेहनत से कुछ दिरहम हज के लिए जमा किए थे, मगर एक दिन देखा कि पड़ौस में गरीब लोग पेट की आग बुझाने के लिए वे चीजें खा रहे हैं, जिन्हें खाया ही नहीं जा सकता। उनकी बेबसी ने मेरा दिल हिला दिया और हज के लिए जो रकम जमा की थी, उन गरीबों में बांट दी। अब हज पर जाऊंगा भी तो कैसे। कोई सूरत नजर नहीं आती। इस तरह अब्दुला बिन मुबारक समझ गए कि उस शख्स को हज पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीन-दुखियों की मदद ही सच्ची तीर्थयात्रा है।

न्यूज

पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति से बात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुअल मैक्रो से सोमवार की रात बात की और आतंकवाद, कट्टरवाद के विरुद्ध फ्रांस के संघर्ष में भारत की ओर से पुरजोर समर्थन व्यक्त किया। श्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से उनके देश में आतंकवादी हमलों पर शोक व्यक्त किया और आतंकवाद, उग्रवाद एवं कट्टरवाद के विरुद्ध उनके संघर्ष में भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया। दोनों ने समान हितों के वैश्विक, क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सस्ते एवं सर्वसुलभ कोविड टीके, कोविड पश्चात अर्थव्यवस्था, हिन्द प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग एवं साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के मुद्दे शामिल हैं।

सपना का गाना नहीं बजाने पर युवक की हत्या, 4 गिरफ्तार

बुलंदशहर, (एजेंसी)। यूपी के बुलंदशहर जनपद में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी का गाना नहीं बजाने पर एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, बताया जा रहा है कि शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर सोमवार देर रात दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद युवक को बुलंदशहर जनपद के हायर सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना को देखते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की सूचना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

85 वर्ष के हुए बॉलीवुड के हीमैन धर्मेन्द्र

मुंबई, (एजेंसी)। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का अपना दीवाना बनाने वाले हीमैन धर्मेन्द्र मंगलवार को 85 वर्ष के हो गए। पंजाब के फगवारा में 08 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेन्द्र का रुझान बचपन के दिनों से ही फिल्मों की ओर था और वह अभिनेता बनना चाहते थे। वर्ष 1958 में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर पत्रिका फिल्म फेयर ने एक विज्ञापन निकाला, जिसमें नए चेहरों को बतौर अभिनेता काम देने की पेशकश की गई थी। धर्मेन्द्र इस विज्ञापन को पढ़कर काफी खुश हुए और अमेरीकन टयूबवेल की नौकरी को छोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए मायानगरी मुंबई आ गए और फिर फिल्मी सफर शुरू किया।

बाइडेन शुक्रवार को करेंगे रक्षा मंत्री के नाम की घोषणा

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह शुक्रवार को रक्षा मंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। श्री बाइडेन ने सोमवार को रक्षा मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल के चयन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि मैं आपके लिए बुधवार तथा शुक्रवार को घोषणा करूंगा। रक्षा से संबंधित घोषणा शुक्रवार को।' उम्मीद जताई जा रही है कि श्री बाइडेन बुधवार को अटॉर्नी जनरल के नाम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इस बार में उन्होंने संवाददाताओं के सवालों का साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के पूर्व नीति प्रमुख मिशेल फ्लॉरनॉय और सेवानिवृत्त सेना जनरल लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री की रेस में सबसे आगे हैं।

अफगानिस्तान में 16 तालिबान आतंकी ढेर, 11 घायल

काबुल, (एजेंसी)। अफगानिस्तान के मध्य प्रांत उरुजगन की सुरक्षा चौकियों पर हमले का प्रयास करने वाले आतंकवादियों में 16 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया तथा इस कार्रवाई में 11 अन्य घायल हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तालिबानी आतंकवादियों ने उरुजगन प्रांत के डेहरा वुड और गिजाब जिलों में स्थित सुरक्षा चौकियों पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि सेना ने आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार एवं गोले बारूद भी बरामद किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को दक्षिणी मेंवांड जिले में सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान तालिबान का एक शीर्ष कमांडर अनास चार अन्य आतंकवादियों के साथ मारा गया।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे!
कोरोना वायरस से
सावधान रहे
क्योंकि सावधानी
ही बचाव हैं।
कोरोना को धोना हैं।

बड़ा खुलासा : क्राइस्टचर्च मस्जिद का हमलावर आया था भारत

ब्रेंटन टैरेंट ने भारत में गुजारे थे तीन माह

क्राइस्टचर्च, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर की दो मस्जिदों में पिछले साल हुए हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस हमले को अंजाम देने वाला ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रेंटन टैरेंट ने भारत सहित दुनियाभर की यात्रा की। उसने भारत में करीब तीन महीने गुजारे थे। इस भयावह गोलीबारी को लेकर जारी की गई एक विस्तृत रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

पांच भारतीयों समेत 51 नमाजी मारे गए थे

गौरतलब है कि 15 मार्च, 2019 को ब्रेंटन टैरेंट ने क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें नमाज पढ़ने आए 51 नमाजियों की मौत हो गई थी। इनमें पांच भारतीय भी शामिल थे। इस हमले में न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी बाल-बाल बचे थे। ये खिलाड़ी गोलीबारी से कुछ देर पहले ही नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल आए थे। इस हमले में दर्जनों लोग घायल हुए थे। गोलीबारी ने न्यूजीलैंड को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसकी गिनती दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों के रूप में होती है।

टैरेंट ने 2012 में छोड़ दी थी जिम की नौकरी

792 पन्नों के रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने रिपोर्ट दी है कि स्कूल छोड़ने के बाद 30 वर्षीय हमलावर टैरेंट ने 2012 तक एक स्थानीय जिम में एक निजी प्रशिक्षक के रूप में काम किया था। 2012 में चोट लगने के बाद उसने जिम की नौकरी छोड़ दी।

पिता के पैसों से घूमने निकला

इसमें कहा गया है कि हमलावर ने जिम की नौकरी छोड़ने के बाद कभी काम नहीं किया। इसकी जगह, उसने अपने पिता से मिले पैसे और इन पैसों को निवेश करने के बाद प्राप्त हुई राशि से घूमना शुरू किया। 2013 में उसने पूरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया घूमा और फिर 2014 से 2017 के बीच उसने दुनिया की बाकी जगहों का दौरा किया।

सबसे ज्यादा वक्त भारत में रहा

18 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि इसने किसी देश में अगर सबसे अधिक समय तक वक्त गुजारा तो वो भारत था। जहां इसने 21 नवंबर, 2015 से 18 फरवरी, 2016 तक का वक्त गुजारा। हालांकि, इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं है कि टैरेंट ने अपने करीब तीन महीने के दौरे के दौरान क्या किया।

हमले की ट्रेनिंग के सबूत नहीं

हालांकि, द न्यूजीलैंड हेराल्ड ने बताया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वह विदेशों में चरमपंथी समूहों के साथ मिला हो। न ही इस बात के सबूत हैं कि उसने विदेश में हमले के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग ली हो।

पाकिस्तान और चीन कुचल रहे धार्मिक आजादी, अमेरिका ने दिखाई सख्ती

दोनों को 10 मुल्कों की निगरानी सूची में डाला

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका ने धार्मिक आजादी के जानबूझकर व अहंकारी उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान व चीन को चिंताजनक स्थिति वाले देश (सीपीसी) के रूप में नामित किया है। अमेरिकी सरकार ने यह कदम सोमवार को उठाया।

इसके साथ ही पाकिस्तान व चीन अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सीपीसी के उन 10 देशों में शामिल हो गए हैं, जो धार्मिक समूहों के उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने में विफल रहे हैं। गौरतलब है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आती रहती हैं। एक आधिकारिक बयान में, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि बर्मा, चीन, इरीट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून (1998) के तहत सीपीसी की सूची में शामिल किया गया है।

कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस भी विशेष निगरानी सूची में : पोम्पियो ने आगे बताया कि कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को एक विशेष निगरानी सूची में रखा गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनियाभर में धार्मिक रूप से प्रेरित दुर्व्यवहारों और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास करता रहेगा और यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अंतरात्मा की आज्ञा के अनुसार जीने का अधिकार रखता है।

चिंताजनक इकाइयों के रूप में इन्हें किया नामित

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त अल-शबाब, अल-कायदा, बोको हरम, हयात तहरीर अल-शाम, हूथी, आईएसआईएस, आईएसआईएस-ग्रेटर सहारा, आईएसआईएस-पश्चिम अफ्रीका, जमात नस्र अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिन और तालिबान को 2016 के फ्रैंक आर वुल्फ इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष रूप से चिंताजनक इकाइयों के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सूडान और उजबेकिस्तान को पिछले साल उनकी सरकारों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण और ठोस प्रगति के आधार पर विशेष निगरानी सूची से हटा दिया गया है।

उत्साह

तिरुवनंतपुरम में मंगलवार को केरल के स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान वोट डालने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं।

कोरोना वायरस वैक्सीन

ब्रिटेन में 90 साल की दादी को लगा फाइजर का पहला टीका

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ब्रिटेन की एक 90 वर्षीय दादी मार्गरेट कीनन क्लीनिकल अप्रूवल के ट्रायल के बाहर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई हैं।

एनिस्किलेन की रहने वाली मार्गरेट कीनन ने टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें बहुत खास महसूस हो रहा है। उन्हें कोवेंट्री के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में टीका लगाया गया है। टीका लगने के बाद

मार्गरेट कीनन ने कहा कि यह सबसे अच्छा प्री बर्थडे गिफ्ट है, जो मुझे पसंद आया, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अंत में अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल में सबसे ज्यादा समय बिताने के लिए ठीक रह सकती हूं।

बीबीसी की खबर के मुताबिक मार्गरेट कीनन दुनिया की ऐसी पहली व्यक्ति हैं, जिन्हें ट्रायल से इतर फाइजर/बायोनटेक कोविड-19 का टीका लगाया गया है। ब्रिटेन की दवा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन नियामक एजेंसी (एमएचआरए) ने पिछले हफ्ते इस टीके को मंजूर दी।

बड़ोदरा में तैयार हो रहे आगरा मेट्रो के कोच

आगरा, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि आगरा मेट्रो में चलने वाले कोच बड़ोदरा (गुजरात) में तैयार हो रहे हैं। इन कोचों को एस्टर्म इंडिया कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसको तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी सफर कर सकेंगे। साथ ही मेट्रो लाइट, मेट्रो वाटर और मेट्रो न्यू योजना की भी जल्द शुरुआत होगी।

वन नेशन वन कार्ड से भी कर सकेंगे सफर

मिश्र ने कहा कि मेट्रो पर पूरे देश में एक साथ काम चल रहा है। वर्ष 2022 में देश की 75वीं जयंती पर एक हजार किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क दिखने लगेगा। एक करोड़ लोग इनमें यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले 12 करोड़ रुपए में एक कोच खरीदना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही इसका निर्माण होने लगा है। अब एक कोच आठ करोड़ रुपए में पड़ता है। उन्होंने बताया कि देश में मेट्रो, बसों और टोल प्लाजा पर एक ही कार्ड काम करेगा। ये पार्किंग में भी चलेगा।

जून 2021 में शुरू हो जाएगा मेट्रो वाटर चलाने का काम

उन्होंने बताया कि मेट्रो वाटर चलाने का काम जून 2021 में शुरू हो जाएगा। 2022 में 72 किलोमीटर की वाटर मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। मेट्रो लाइट का पिछले साल 2019 में शुभारंभ किया गया था। इसे इलाहाबाद और गोरखपुर जितनी आबादी वाले शहरों में शुरू करने की योजना है। एक किलोमीटर में एलीवेटेड बनाने पर 300 करोड़ और भूमिगत बनाने पर एक किलोमीटर में 600 करोड़ का खर्च आएगा। मेट्रो न्यू को 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में शुरू किया जाएगा। इसे टायरों पर चलाया जाएगा। इस पर एक किलोमीटर में 50 से 60 करोड़ रुपए का ही खर्च आएगा। वहीं प्रदेश के सात शहरों में 131 किलोमीटर मेट्रो लाइन का काम चल रहा है।

ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो में लिखा होगा 'मेड इन इंडिया' : ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों में दौड़ने वाली मेट्रो पर 'मेड इन इंडिया' लिखा दिखेगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि मिडिल ईस्ट और एशिया के कई अन्य देशों में भी भारत में बनी मेट्रो चलेगी।

भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान ने रची नई साजिश

आईएसआई ने इस्लामाबाद में मौजूद विदेशी दूतावासों के डिफेंस अटैची को बुलाया

नई दिल्ली ■ एजेंसी

अपने आका चीन को खुश करने के लिए और खुद को एफएटीएफ के जाल से बचाने के लिए पाकिस्तान की भारत को बदनाम करने की एक और नापाक चाल सामने आई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शुक्रवार को अपने मुख्यालय में पाकिस्तान में मौजूद सभी विदेशी दूतावासों के डिफेंस अटैची को बुलाकर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रही है।

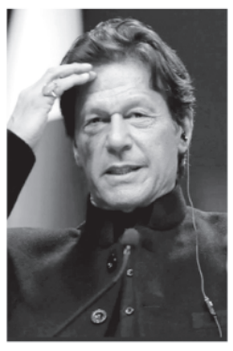

अपने आका चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसके तहत अब पाकिस्तान ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए एक और प्रोपेगेंडा करने की साजिश रची है। इस साजिश के तहत पाकिस्तान ने अपने देश में मौजूद सभी विदेशी देशों के दूतावासों से उनके डिफेंस अटैची को 11 दिसंबर को आईएसआई मुख्यालय में भेजने को कहा है। पाकिस्तान सरकार के दस्तावेज के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद सभी विदेशी दूतावासों को पत्र भेजा गया है।

भारत के खिलाफ फैलाना चाहती है फिर से प्रोपेगैंडा

खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की बैठक का मकसद एकदम साफ है। आईएसआई इस बैठक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगैंडा फैलाना चाहती है, साथ ही वह फरवरी में होने वाली एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को भी बचाना चाहती है, जिससे वह इल्जाम भारत के सिर पर थोपकर खुद को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर करा सके।

आईएसआई के महानिदेशक ताजा हालातों से कराएंगे अवगत

इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के महानिदेशक इन दूतावासों के डिफेंस अटैची को ताजा हालातों से अवगत कराएंगे। इस दस्तावेज के मुताबिक विदेशी डिफेंस अटैची को भारत-पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूदा स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर वर्तमान में क्या हालात हैं, उनके बारे में अवगत कराया जाएगा, साथ ही पाकिस्तान आतंकवाद निरोधक मामलों में कौन से कदम उठा रहा है, इस बारे में भी विदेशी दूतावास के लोगों को अवगत कराया जाएगा।

आंध्र में अज्ञात बीमारी से 500 लोग पीड़ित, एक मौत ने बढ़ाई चिंता

अमरावती, (एजेंसी)। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोग पहले से ही बुरी तरह परेशान हैं आंध्र प्रदेश में 500 लोग एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए हैं और अपनी इलाज करवा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एलुरू में शनिवार को सबसे पहले आए इस मामले के बाद सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट को इसका पता लगाने के लिए भेज दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर लोग इससे फौरन ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत ने इसको लेकर चिंता बढ़ा दी है। इधर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एलुरू में सामने आई रहस्यमयी मौत को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सतर्कता बरते और वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए संभावित सभी तरह के जांच कराएं। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों से कहा है कि वे बीमारियों के बारे में और जो टेस्ट्स और इलाज किया जा रहा है उसके लेकर व्यापक रिपोर्ट सौंपे। इसके साथ ही, दूध और पानी को लेकर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी दें।

सीएम रेड्डी ने दिए बीमारी का पता लगाने के निर्देश

गौरतलब है कि एलुरु शहर के विद्यानगर इलाके के 45 वर्षीय व्यक्ति की रविवार शाम को बीमारी के कारण मौत हो गई। इनकी पहचान श्रीधर के रूप में हुई है। उन्हें सुबह मिर्गी और जी मिचलाने के लक्षणों के साथ स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार श्रीधर शाम तक अपने मिर्गी के लक्षणों से उबर चुके थे। उनकी मौत अन्य सिम्टम्स से हुई। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से ताल्लुक रखने वाले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इस बारे में बातचीत की। एलुरु में बड़ी संख्या में बच्चों समेत अन्य लोगों को इस रहस्यमयी बीमारी का पता चलने के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

खुलासा

नेपाल और चीन ने मापकर दुनिया को बताया

घटी नहीं, बढ़ गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई

काठमांडू, (एजेंसी)। दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसकी माप के संबंध में इकट्ठा किए गए डाटा एक साल तक खंगालने के बाद नेपाल सरकार ने मंगलवार को माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा की। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो पहले के मुकाबले 2.8 फीट ज्यादा है।

भूकंप के बाद ऊंचाई घटने का अनुमान था

2015 में नेपाल में आए भयंकर भूकंप के बाद व्यापक रूप से यह माना जाता था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर नहीं रही है, इसलिए नेपाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई मापने की तैयारी की। इसके बाद

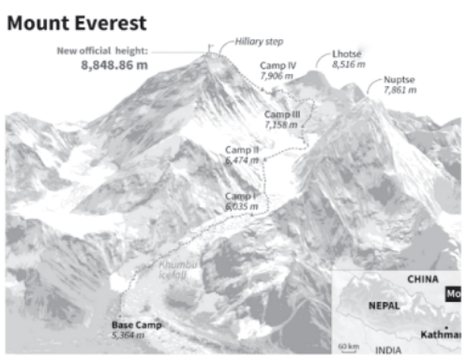

मंगलवार को नेपाल के विदेश मंत्री ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8848.86 मीटर बताई है।

वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर

चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई नापी गई ऊंचाई के बाद इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी घोषित की है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। एवरेस्ट अब पहले की तुलना में 2.8 फीट लंबा है।

अधिकारियों और विशेषज्ञों को पहाड़ की ऊंचाई मापने किया तैनात

नेपाल ने अधिकारियों और विशेषज्ञों को पहाड़ की ऊंचाई को फिर से मापने के लिए तैनात किया। इसके अलावा, नेपाल सरकार ने भी अपने घरेलू प्रयासों में चीन के साथ मिलकर काम किया। 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई की घोषणा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

गैंगस्टर सुख भखारीवाल को दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पंजाब के गैंगस्टर सुख भखारीवाल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। भखारीवाल शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू की हत्या का मास्टरमाइंड है। वहीं अब माना जा रहा है कि सुख भखारीवाल को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। दुबई पुलिस ने भखारीवाल को हिरासत में लिया है।

बलविंदर संधू की हत्या का है मास्टरमाइंड

दरअसल, एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो पंजाब के भी थे। इनसे पूछताछ के बाद सुख भखारीवाल को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के आतंकियों से मिली जानकारी के बाद दुबई पुलिस ने संपर्क किया गया और सुख भखारीवाल को हिरासत में लेने को कहा गया। वहीं पंजाब एसटीएफ का कुछ महीने पहले अमृतसर के पास जंडयाला में ड्रग स्मगलर्स से एनकाउंटर हुआ था। मौके पर पकड़ा एक स्मगलर गैंगस्टर सुख भखारीवाल का गुर्गा था। उसके फोन से कई मैसेज एसटीएफ को मिले थे, जिनसे पता चला था कि सुख भखारीवाल के तार पाक में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकवादी केजेएफ चीफ रणजीत नीटा से जुड़े हैं, वहीं भखारीवाल को हिरासत में लेने के बाद पंजाब पुलिस भी मामले में एक्टिव है।

प्रस्तावित एम.एस.एम.ईज़ विस्तार केंद्र पंजाब के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में अहम साबित होंगे-सुंदर शाम अरोड़ा

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

नए एम.एस.एम.ई. विस्तार केंद्र पंजाब के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में अहम साबित होंगे। यह नई सुविधाएं रा%य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की पहुँच को बढ़ाने के साथ-साथ विकसित निर्माण तकनीक तक पहुँच मुहैया करवाएँगी। यह प्रगटावा पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने आज यहाँ किया।

श्री अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश भर में हॅब और स्पोक मॉडल के आधार पर 200 करोड़ रुपए (हरेक) की प्रोजैक्ट लागत के साथ 20 नए टैक्नोलॉजी केंद्र (टी.सीज़) और 20 करोड़ रुपए (हरेक) की प्रोजैक्ट लागत के साथ 100 विस्तार केन्द्र (ई.सीज़) स्थापित करने का फ़ैसला लिया है। अपने काम-काज के दो सालों के अंदर मॉडल के स्वै-स्थायी रहने की उम्मीद है।

श्री अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में भारत सरकार के सैंट्रल टूल रूम (सी.टी.आर.), लुधियाना और सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्ज़ (सी.आई.एच.टी.) नामी 2 इंस्टीट्यूट हैं जो पंजाब राज्य में स्थापित होने वाले विस्तार केंद्र के लिए हॅब सैंटर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग एवं वाणि%य विभाग, पंजाब ने एस.ए.एस. नगर, पटियाला, अमृतसर और होशियारपुर की पहचान की है और हाल ही में सैंट्रल टूल रूम, लुधियाना और सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्ज़, जालंधर के साथ विस्तार केन्द्रों (स्पोक सेंटरों) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जहाँ इस मंतव्य के लिए टोकन लीज़ के आधार पर अपनी खाली ज़मीन और इमारतें देने की सहमति बनी। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के अलावा विभाग जालंधर में खेल के सामान की इंडस्ट्री के लिए एक विस्तार केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। व्यावहारिक बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए अरोड़ा ने कहा कि एमएसएमई सैक्टर कम निवेश पर रोज़गार के बड़े मौके प्रदान करता है। नवाचार और रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए यह कम कीमत पर समाधान विकसित करने और नए बिज़नेस मॉडलों का सृजन करने में समर्थ है और इस तरह आर्थिक

विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए एम.एस.एम.ई. अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन की रीढ़ हैं। हालाँकि, इनको प्रौद्योगिकी, कुशल कामगारों और मार्केट तक पहुँच के मामले में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि भारत सरकार के एम.एस.एम.ईज़ संबंधी मंत्रालय ने पहले ही देश भर के बड़े औद्योगिक शहरों में 33 प्रौद्योगिकी सैंटर (टी.सीज़) स्थापित किए हैं। इन टी.सीज़/ई.सीज़ की स्थापना के लिए, यह कल्पना की गई है कि भारत सरकार इस सम्बन्धी सारी मशीनरी/उपकरण प्रदान करेगी और राज्य सरकार विस्तार केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त ज़मीन और इमारत प्रदान करेगी। प्रौद्योगिकी केंद्र (टी.सीज़) राज्य के किसी भी बड़े औद्योगिक शहर में स्थापित होंगे और अत्याधुनिक मशीनरी/उपकरण के साथ लैस होंगे। यह सैंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे और हब्ब सैंटरें के तौर पर काम करेंगे। ज़मीनी स्तर पर एम.एस.एम.ईज़ तक उनकी पहुँच को बढ़ाने के लिए, यह हब्ब सैंटर राज्य के संभावित ज़िलों या कैचमैंट क्षेत्र (पानी वाले क्षेत्र) में अपने विस्तार केन्द्रों की स्थापना करेंगे। यह प्रौद्योगिकी केंद्र नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ लैस होंगे और सम्बन्धित स्पोक्स सेंटरों के लिए काम करेंगे।

यह तकनीकी माहिरों के साथ तालमेल करेंगे, नई प्रौद्योगिकी के लिए लाइसैंसों की खरीद करेंगे और संबंधित स्पोक्स सैंटरों के द्वारा एम.एस.एम.ईज़ को तकनीक मुहैया करवाने में सहायता करेंगे। प्रस्तावित विस्तार केंद्र में सी.ए.डी, केम, सी.ए.ई, सी.एन.सी मशीनों, पी.एल.सी, ऐमबैड्ड सिस्टम, इंडस्ट्री 4.0, वैलडिंग, पीसने, हीट ट्रीटमेंट सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह सुविधाएं क्षेत्र के एम.एस.एम.ईज़ को टूलिंग और उत्पादन सेवाएं प्रदान करेंगी, जिससे इन शहरों में मौजूद उद्योगों की सहायता की जा सकेगी। यह उद्योगपतियों को अपने हब्ब के सक्रिय तकनीकी और व्यापारिक संबंधों के साथ अपना नया उद्योग शुरू करने में सहायता करेंगे। कौशल विकास की गतिविधियों स्थानीय लोगों को ज्ञान और कौशल प्राप्ति के मौके उपलब्ध करवाएँगी, जिससे वह अपने इलाके के उद्योगों में काम कर सकें और स्थानीय आर्थिकता को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकें। टूल एंड डाई टैक्नॉलॉजी, सी.ए.डी, केम, सी.ए.ई, पी.एल.सी, ऐमबैडड सिस्टम, वैलडिंग, हीट ट्रीटमेंट के प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह कोर्स एन.एस.क्यू.एफ की पालना करते हुए 96घंटों से एक साल के हैं और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। यह योजना बनाई गई है कि इनमें से हरेक केंद्र को स्वैचालन, हीट ट्रीटमेंट, वैलडिंग के क्षेत्र में पृथक बनाया जाए और एक्सीलेंस के दूसरे केन्द्रों के साथ जोड़ा जाए जिससे मौजूदा और उभर रहे उद्यमियों को संपूर्ण समाधान मुहैया करवाए जा सकें।

पशु पालन मंत्री तृप्त बाजवा ने 117 वेटनरी अफसरों को नियुक्ति पत्र सौंपे

डेयरी के धंधे को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए बढ़िया नसलों और विदेशी सीमन उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे ने विशेष प्रयास-तृप्त बाजवा

चंडीगढ़/एस.ए.एस. नगर/ब्यूरो

पंजाब सरकार द्वारा घर-घर रोज़गार प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य के पशु पालन, डेयरी विकास और मछली पालन विभाग में 117 वेटनरी अफसरों की भर्ती की गई है। आज यहाँ लाइव स्टॉक भवन में पशु पालन, डेयरी

विकास और मछली पालन मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने नव-नियुक्त वेटनरी अफसरों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

इस मौके पर नव-नियुक्त वेटनरी अफसरों को बधाई देते हुए श्री तृप्त बाजवा ने बताया कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में राज्य के अधिक से अधिक नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए अफसरों की तैनाती के साथ पशु पालन विभाग के काम को और गति मिलेगी और पशु पालकों को और बढ़िया सेवाएं मिलेंगी।

पशु पालन मंत्री ने कहा कि पशु पालन विभाग में काम करने वाले डॉक्टर मनुष्यों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की सेवा की अपेक्षा भी बड़ी है, क्योंकि वह बेजुबानों का इलाज करते हैं, जो खुद बोलकर अपना दुख दर्द नहीं बता सकते।

उन्होंने कहा कि बेजुबानों की बीमारी का खुद पता लगा कर उनको तंदुरुस्त करने के कारण उनकी सेवा बड़ी है, जिसके लिए वे आशीर्वाद के पात्र भी बनते हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि पशु पालन विभाग द्वारा उच्चतम नसल और विदेशी सीमन/भ्रूण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे दूध के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। इस मौके पर पशु पालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री वी.के. जंजूआ ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पशु पालन विभाग द्वारा किसानों/पशु पालकों के पशुधन की नसल सुधार के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे डेयरी के पेशे को राज्य में और विकसित करके लोगों के लिए और अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। उन्होंने इसके साथ ही बताया कि पशु पालकों के लिए कल्याण स्कीमों को सुचारू ढंग से लागू किया जा रहा है और पशु पालकों की सहायता के लिए विभाग द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर वाइंट डायरैक्टर पशु पालन डॉ. एच.एस. काहलों ने और पंजाब स्टेट वेटनरी अफसर एसोसिएशन के प्रधान डॉ. सरबजीत सिंह रंधावा के अलावा विभाग के अन्य सीनियर अफसर भी मौजूद थे।

बीजेपी जालंधर लीगल सेल के प्रधान एडवोकेट लखन गांधी ने योगराज सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई

जालंधर ब्रीज/रवि

योगराज सिंह के विवादित बयान के बाद बीजेपी लीगल के जिला प्रधान लखन गांधी ने उसकी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने डी.सी.पी बलकार सिंह को मांग पत्र दिया। हिंदुओं पर की विवादित टिप्पणी किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदुओं को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। योगराज ने किसान आंदोलन के दौरान भाषण में हिंदुओं को लेकर ऐसी

टिप्पणी की है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। योगराज के भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो को देखने के बाद लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये बोले योगराज सोशल मीडिया पर वायर हो रहे वीडियो में योगराज सिंह पंजाबी भाषा में भाषण दे रहे हैं। भाषण के दौरान वह हिंदुओं के लिए 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। योगराज कहते हैं कि, 'ये हिंदू गद्दार हैं, सौ साल मुगलों की गुलामी की'। इतना ही नहीं, उन्होंने हिन्दू महिलाओं को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया है जिसमे वोह कहते है इनकी औरतें टक्के-टक्के के भाओ भिक्ती है इसके सम्बन्ध मै एडवोकेट लखन गांधी के साथी एडवोकेट रॉबिन युवा नेता ने कहा कि जो शब्द योगराज सिंह ने बोले है हम हिंदुओ के दिल पर बहुत ठेस पहुंची है ओर योगराज सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है इसके सम्बन्ध में एडवोकेट दविंदर राणा,एडवोकेट गोमती भगत, एडवोकेट प्रदीप ,एडवोकेट गौरव एडवोकेट रोहित, एडवोकेट अश्वनी कुमार मांग पत्र देते हुए उपस्थित थे।

छत्तबीड़ चिड़ियाघर 10 दिसंबर से नए दिशा- निर्देशों के साथ सैलानियों के लिए दोबारा खुलेगा

चंडीगढ़/एसएएस नगर/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने वन एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और चिड़ियाघर सैलानियों, कर्मचारियों और पशुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कोविड-19 प्रोटोकोल की पालना करते हुए 10 दिसंबर, 2020 से छत्तबीड़ चिड़ियाघर को दोबारा खोलने के लिए मंज़ूरी दे दी है। यह जानकारी फील्ड डायरैक्टर एम.सी. ज़ूलोजीकल पार्क, छत्तबीड़ डॉक्टर एम. सुधागर ने दी। पहली बार सैलानियों को शेर के बच्चे अमर, अर्जुन और दिलनूर को देखने का मौका मिलेगा।

इसके साथ ही भारतीय लोबड़ी को अपने नए जन्मे बच्चों के साथ पहली बार देखा जा सकेगा। इसके अलावा, चिड़ियाघर में सैलानियों के लिए बहुत सी नयी सुविधाएं जैसे मॉम एंड बेबी केयर रूम, मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट, कॉफ़ी बूथ, कंट्रोल रूम, सैल्फी प्वाइंट्स, नया आराम घर, परेशानी रहित पार्किंग, टच्च फ्री हैंड वॉश और सैनीटाईजर डिस्पेंसर भी दिए जा रहे हैं। लोगों की माँग और सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने छत्तबीड़ चिड़ियाघर और आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर अमल करते हुए चिड़ियाघर को दोबारा खोलने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है।

प्रति स्लॉट में 900 सैलानियों की एंट्री के साथ एक दिन में अधिक से अधिक 2700 सैलानियों को एंट्री की होगी आज्ञा

कोविड अनुकूल व्यवहार पर पांच दिवसीय आउटडोर जागरूकता अभियान शुरू मोहाली नगर-निगम आयुक्त ने जागरूकता मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा नगर निगम मोहाली के सहयोग से जिला मोहाली में कोविड के प्रकोप से बचने के लिये कोविड अनुकूल व्यवहार से संबंधित जागरूकता हेतु 5 दिवसीय आउटडोर जागरूकता अभियान 09 से 13 दिसंबर, 2020 तक आयोजित किया गया है

इस अवसर पर एक जागरूकता मोबाइल वैन को मोहाली नगर निगम के आयुक्त श्री कमल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर नगर निगम कार्यालय मोहाली से रवाना किया तथा कहा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं उनको कोरोना की दवा आने तक संयम बनाए रखने तथा अपने बचाव के लिए कोविड अनुरूप

व्यवहार अपनाने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में मिशन फतेह के जरिए भी लोगों को इस संदर्भ में जागरूक किया गया था।

इस अवसर पर नगर निगम के अन्य अधिकारियों में सुश्री कनु थिंद, संयुक्त आयुक्त ; श्री सुरजीत सिंह, सहायक आयुक्त; श्री हरबंत सिंह सेनेटरी इंस्पेक्टर; श्री सरबजीत सिंह, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो, चण्डीगढ़,सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की स सहायक निदेशक सुश्री सपना ने जानकारी दी कि यह अभियान केंद्र सरकार द्वारा पिछले माह चलाए गए जन आंदोलन की एक कड़ी है जिसके द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है यह अभियान देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को रोकने तथा लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोरोना से बचाव के लिए मुख्य संदेशों को दोहराना है जिसमें मास्क पहने रखना हाथ धोना तथा सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी का पालन करना शामिल है इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड से संबंधित नए नियमों के प्रति उत्साहित करना है। जागरूकता वैन में प्रदर्शित कोरोना से संबंधित संदेशों को लेकर यह वाहन मोहाली जिला के सैक्टरों,गांवों, रिहायशी कॉलोनियों, प्रवासी बस्तियों, बाजारों आदि में घूमेगा और लाउडस्पीकर के जरिए ऑडियो संदेशों के माध्यम से लोगों को जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश का आह्वान करेगा।

स्पोर्ट्स प्लैनट

कप्तान कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही वनडे में सबसे कम पारियों में 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है।

9 जनवरी को होगा I-LEAGUE का आगाज, इन दो टीम के बीच होगी कांटों की टक्कर

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

हीरो आईलीग फुटबॉल का आगाज नौ जनवरी को कोलकाता में सुदेवा दिल्ली एफसी और मोहम्मडन एफसी के बीच मैच से होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मंगलवार को कार्यक्रम की घोषणा की। कोरोना महामारी के कारण लीग के सारे मुकाबले दर्शकों के बिना खेले जायेंगे। ये मैच विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन, कल्याणी म्युनिसिपल स्टेडियम और किशोर भारती क्रीडांगन में होंगे। पहले दिन टूर्नामेंट की नयी टीम सुदेवा का सामना मोहम्मडन एससी से होगा। इसके बाद राउंडग्लास पंजाब एफसी और एजल एफसी के बीच मैच होगा। आयोजकों ने 11 टीमों की

लीग के पहले हाफ का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसमें 24 फरवरी तक दस दौर के मैच होंगे। इसका प्रसारण वन स्पोटर्स पर किया जायेगा और सोशल मीडिया . ओटीटी पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तमाम खिलाड़ी, अधिकारी , रैफरी और अन्य मैच अधिकारी बायो बबल में रहेंगे।

क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

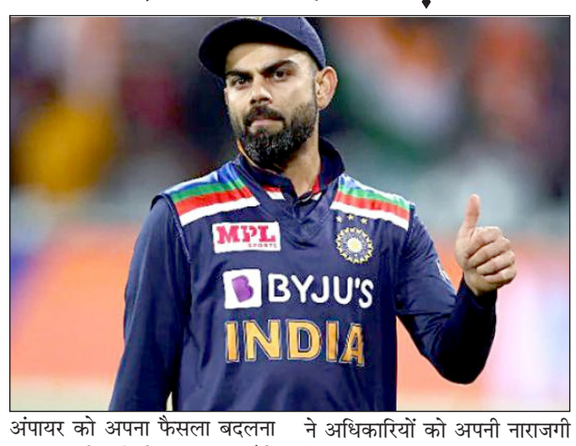

भारत के लिये 17 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पार्थिव पटेल ने बुधवार को खेल के तमाम प्रारूपों को अलविदा कह दिया। तीन महीने बाद अपना 36वां जन्मदिन मनाने जा रहे पार्थिव ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिखा ,'' मैं आज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से विदा ले रहा हूं। भारी मन से अपने 18 साल के क्रिकेट के सफर का समापन कर रहा हूं। '' सौरव गांगुली की कप्तानी में 17 वर्ष 153 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पार्थिव ने 65 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जिनमें 25 टेस्ट, 38 वनडे और दो टी20 मैच शामिल है। उन्होंने 1696 रन बनाये जिसमें टेस्ट क्रिकेट में 934 रन शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने चार अर्धशतक समेत 736 रन बनाये। इसके अलावा बतौर विकेटकीपर टेस्ट में 62 कैच लपके और 10 स्टम्पिंग की। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड दौरे पर भेजा गया जब उन्होंने रणजी ट्राफी क्रिकेट में भी पदार्पण नहीं किया था। पार्थिव ने कहा ,'' बीसीसीआई ने काफी भरोसा जताया कि 17 साल का एक लड़का भारत के लिये खेल सकता है। अपने कैरियर के शुरूआती वर्षों में मेरी इस तरह हौसलाअफजाई करने के लिये मैं बोर्ड का शुक्रगुजार हूं।'' उन्होंने 2004 में भारतीय टीम से बाहर किये जाने के बाद पहला रणजी मैच खेला। पार्थिव ने 'दादा' यानी बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली समेत सारे कप्तानों को धन्यवाद दिया। महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद पार्थिव विकेटकीपर के तौर पर दूसरी पसंद हो गए और यदा कदा बतौर बल्लेबाज ही खेले। बाद में सीमित ओवरों में सलामी बल्लेबाज के रूप में कुछ मैच खेले। पार्थिव ने लेकिन हमेशा स्वीकार किया कि वह धोनी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें और दिनेश कार्तिक को धोनी से पहले टीम में अपनी जगह पक्की करने के

मौके मिले थे। वह घरेलू क्रिकेट में काफी कामयाब रहे और 194 प्रथम श्रेणी मैचों में 27 शतक समेत 11240 रन बनाये। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये खेला। इस बार आरसीबी के लिये वह एक भी मैच नहीं खेल सके। उन्होंने कहा ,'' मैं आईपीएल टीमों और उनके मालिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे टीम में शामिल किया और मेरा ध्यान रखा।'' पार्थिव की कप्तानी में गुजरात ने 2016-17 में रणजी खिताब जीता। वह भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पहले कप्तान रहे जिनके साथ2 2013 में सैयद मुश्ताक अली ट्राफी खेला। पार्थिव ने कहा ,'' मुझे सुकून है कि मैने गरिमा, खेल भावना और आपसी सामंजस्य के साथ खेला। मैने जितने सपने देखे थे, उससे ज्यादा पूरे हुए। मुझे उम्मीद है कि मुझे याद रखा जायेगा।

DRS पर बोले Virat Kohli, 15 सेकंड से पहले स्क्रीन पर रिप्ले दिखाना महंगा पड़ा

■ सिडनी/ब्यूरो

भारतीय कप्तान विराट कोहली इस बात से नाखुश है कि मैथ्यू वेड को डाली गई गेंद पर रिप्ले बड़ी स्क्रीन पर 15 सेकंड से पहले दिखाये जाने के कारण उनकी टीम डीआरएस नहीं ले सकी। भारत को तीसरे टी-20 मैच में 12 रन से पराजय झेलनी पड़ी। वेड को टी नटराजन ने 50 के स्कोर पर पगबाधा आउट कर दिया था लेकिन उन्हें इस तरह जीवनदान मिला और उन्होंने 30 रन और बनाये। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' हम 15 सेकंड की समयसीमा के भीतर बात ही कर रहे थे कि गेंद कहां पड़ी है कि स्क्रीन पर रिप्ले आ गया।'' उन्होंने कहा ,'' हमने रिव्यू लिया लेकिन अंपायर ने कहा कि स्क्रीन पर रिप्ले आ चुका है।'' रिव्यू लिया होता तो मैदानी

अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता। कोहली ने कहा ,'' मैने अंपायर रॉड टकर से बात की। मैने पूछा कि इस हालत में क्या करना है तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, यह टीवी की गलती है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय टीम प्रबंधन ने अधिकारियों को अपनी नाराजगी से अवगत कराया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच में इस तरह की गलती अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, '' टीवी टीम की एक मामूली गलती इतनी भारी पड़ सकती है। उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा।

14 साल में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी दक्षिण अफ्रीकी टीम

■ जोहान्सबर्ग/ब्यूरो

दक्षिण अफ्रीका अगले साल जनवरी-फरवरी में दो टेस्ट और तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी. 2007 के बाद यह पहली बार होगा कि दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान का दौरा करेगी।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी और 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले क्वारंटीन रहेगी। यह टेस्ट सीरीज आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा होगी, जिसका दूसरा टेस्ट चार फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा।

इसके बाद टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। इस सीरीज के तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। क्रिकबज ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के निदेशक ग्रीम स्मिथ के हवाले से लिखा, यह देखना संतोषजनक है कि कई देश पाकिस्तान लौट रहे हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका उन देशों में गिने जाने से खुश है। मैंने एक बार से ज्यादा पाकिस्तान का दौरा किया है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट को लेकर कितने जुनूनी हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.